







## लोकतंत्र स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं

सत चरणों में कराए जा रहे आम चुनाव-24 के प्रथम चरण में 2019 की तुलना में करीब चार फीसद कम मतदान होने से चुनाव आयोग, राजनीतिक दल गरज यह कि चुनाव प्रक्रिया से संबद्ध सभी पक्ष चिंता में पड़ गए हैं। गौरतलब है कि अठारहवें लोक सभा के लिए प्रथम चरण का मतदान अपेक्षाकृत धीमी गति से शुरू हुआ लेकिन दिन चढ़ने के बाद भी धीमापन आखिर तक बरकरार रहा। मतदान के एक दिन बाद ही शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मतदाताओं से अपील की कि मतदान, चाहे किसी को भी बोट करें, में जरूर हस्ता लें। कम मतदान के कारणों की पड़ताल शुरू हो चुकी है, और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कई राज्यों में लू की स्थिति, शादियों के मुहूर्त और मतदाताओं में उत्साह की कमी के चलते मतदान फीसद में गिरावट आई है। चार फीसद कम मतदान का मतलब हुआ कि पिछली बार की तुलना में इस बार करीब 48 लाख मतदाता मत देने नहीं पहुंचे। मतदान का पहला चरण बाकी के चरणों का रुख तय करता है, जैसा कि पिछले दो संसदीय चुनावों के आंकड़ों से पता चलता है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि बाकी बचे छह चरणों में भी मतदाताओं में उदासीनता का रुख बना रह सकता है, जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। यह सवाल परेशानी का सबब बन चुका है कि आखिर, शिक्षित मतदाता तक अपने मताधिकार का उपयोग करने के प्रति इस कदर गैर-जिम्मेदाराना रवैया क्यों अपना रहा है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि देश के नागरिक का अपने देश के प्रति, लोकतंत्र के प्रति दायित्व सर्वोपरि है। यदि नागरिक इस प्रकार से मतदान के प्रति बेरुखी दिखाएँगा तो लोकतंत्र कैसे समृद्ध बना रह पाएगा। आने वाले छह चरणों में भी मतदाता का यही रुख न बना रहे इसके लिए समन्वित प्रयास करने जरूरी हैं। हालांकि चुनाव आयोग चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए खासे प्रयास अरसे से करता रहा है। इस क्रम दस से ज्यादा मशहूर हस्तियों को राजदूत के रूप में नियुक्त करने के साथ ही आईपीएल दर्शकों के बीच मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया गया।

## विचार

# राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र चुनाव आयोग में पंजीकृत हो....

लोकतांत्रिक देशों में चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी करने का चलन रहा है। दरअसल घोषणा पत्र का चलन संबंधित पार्टी के द्वारा आने वाले समय में कौन से काम को हाथ में लेंगे और क्या होना चाहिए इसका एक विवरण या पांच वर्षीय कार्यक्रम जैसा होता है। परंतु पिछले कुछ दशकों से यह अनुभव हो रहा है कि राजनीतिक दल विशेषतरूप जो सत्ताधारी या सत्ता के नजदीक हैं, वह घोषणाएं तो बहुत करते हैं परंतु उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं। घोषणा पत्रों के स्वरूप भी अब बदल रहे हैं। 1952 से लेकर 1967 तक के दलों के चुनाव घोषणा पत्रों को देखें तो उनमें मुख्यतरूप नीति परिवर्तन के संदेश और वायदे ज्यादा होते थे। परंतु अब घोषणा पत्र नीति परिवर्तन के बजाय वोट खरीदने के मंत्र बन रहे हैं। और घोषणा पत्र में मुख्यतरूप राहत की बातों की चर्चा ही मुख्य होती है कि अगर सरकार बनती है तो कौन-कौन सी रियायत मतदाताओं को देंगे। मैं रियायतों के खिलाफ नहीं हूँ। परंतु रियायतें स्थानी नहीं होनी चाहिए वरना वह लोकतांत्रिक विफलता में बदल सकती हैं। रियायतें एक अस्थाई संक्रमणता व्यवस्था हो जो आमजन को समर्थ बनाने की अवधि के बीच की मदद हो परंतु आमतौर पर दलों का लक्ष्य स्थाई विकलांगता पैदा करना हो गया यानि समर्थ न बनाकर निन्तर कमज़ोर रखना तथा मदद के नाम पर वोट हासिल करते रहना एक स्थाई रणनीति बन गई है। इस 2024 के लोकसभा चुनाव का जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है उसमें यह कहा है कि गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। भारतीय जनता पार्टी भी इसके पहले चुनाव में लगभग ऐसी ही अन्य घोषणाएं करती रही। उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 500 रुपए तक के किसानों के कर्ज़ों को छोड़ दिया था। यह एक अन्य घोषणा है कि जनता पार्टी ने अपने लोकतांत्रिक विफलता में लागू करने का प्रयत्न करेगी, ताकि किसानों की फसलों की रक्षा हो सके, सड़कों पर यातायात ठीक हो सके और गौवंश को रैन-बर्सेरा प्राप्त हो सके भारतीय सभ्यता में गाय को सदैव देवी माता स्वरूप माना जाता है। भारत में गोपालन की प्राचीन काल से ही परंपरा रही है। इसलिए उस समय धीरे, दूध और दही की नदियां बहती थीं। ऋषियों के आश्रम जंगलों में होते थे। वहां हजारों गढ़ एं स्वतंत्र रूप से विचरण करती और जंगलों में चरती थीं। भगवान श्रीकृष्ण जी ने द्वापर युग में खुद गऊओं की सेवा की। इसलिए उनका एक नाम श्री गोपाल आज भी संसार भर में प्रसिद्ध है। भगवान ने मानव जाति को गाय वरदान स्वरूप दी थी, लेकिन आज का स्वार्थी मानव गाय को आप्त समझ रहा है। वह दिन दूर नहीं जब गाय के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। जब गाय नहीं होगी तो किसान नहीं होगा। जब किसान नहीं होंगे तो गांव भी नहीं होंगे। जब गांव नहीं होंगे तो देश नहीं होगा। धीरे-धीरे तेल के भंडार कम हो रहे हैं। जब तेल खत्म हो जाएगा, तब खेती के लिए बैलों की ज़रूरत होगी, लेकिन क्या तब तक बैल बच पाएंगे? खेद है कि 33 करोड़ देवी-देवताओं को धारण करने वाली, पंचगव्य देने वाली, सूतक-पातक से बचाने वाली गाय माता आज जूठन खा रही है, पत्थर व डंडे खा रही है। वाईयो

रणजात राणा

# आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता द्वा क्षेत्र

डा. अश्विनी महाजन

प्रत्याशियों के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर मतदाताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाना या कोई सुविधा देना चुनावी कानून की दृष्टि से अपराध है और इस अपराध के लिए उनके चुनाव भी रद्द हो सकते हैं, परंतु राजनीतिक दलों के द्वारा घोषणा पत्र के नाम पर यह थोकबंद खरीद चुनावी अपराध नहीं मानी जाती। सार्वजनिक रूप से ऐलान करके इस प्रकार से मतदाताओं को ललचाते हैं और बोट लेते हैं। घोषणा पत्र जारी करने की प्रक्रिया में एक और परिवर्तन आया है कि आम तौर पर घोषणा पत्र पार्टियां बगैर किसी सामाजिक और आर्थिक आंकलन के करती हैं। 1952 के बाद लगभग 2-3 दशकों तक पार्टियां जो घोषणा पत्र जारी करती थीं उनके पीछे एक उत्तरदायित्व की भावना तथा वस्तुपरक आंकलन होता था कि वहघोषणा कैसे पूरी कर सकेंगे? जिनके लिए वे जरूरी मानती हैं। व्या देश के आर्थिक हालात इसके लिए समर्थ होंगे। मुख्यतर उनके चुनाव घोषणा पत्र में नीति निर्माण के ऊपर जोर दिया जाता था। अब पार्टियों के जो घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं वह इन्हें लंबे चैड़े हो रहे हैं कि उन्हें याद रखना जनता को तो दूर पार्टी के नेताओं को भी याद रखना संभव नहीं बचा है। पाँच सौ हजार वायदे और अलग-अलग क्षेत्रों के वायदे वाले इन चुनाव घोषणा पत्रों में सौ-सौ पेज तक होते हैं। इन चुनाव घोषणा पत्र को ना तो पार्टी वाले और ना मतदाता पढ़ते हैं। कोई विशिष्ट मुद्रे पर या किसी विशिष्ट राहत की घोषणा पर देश में चर्चा हो जाती है, परंतु उसका कोई महत्व नहीं होता। अभी जो चुनाव घोषणा पत्र जारी हुए हैं इनमें उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने भी कल घोषणा की है कि छोटे किसानों को प्रति माह प्रति किसान रु. 5000 की सहायता दी जाएगी। यह ढाई एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को दी जाएगी। मैं नहीं जानता हूं कि उन्होंने इसका कोई आंकड़ा निकाला है? क्योंकि अगर निकाला होता तो वह उनकी भी संख्या भी जारी करते। इसी प्रकार हर मजदूर को रु. 5000 प्रतिमाह पेंशन देने का वादा किया है। सामान्य मजदूरी वाले मजदूरों की संख्या अनुमानतरूप देश में (खेती और गैर खेती वाले मिलाकर) लगभग 30 करोड़ के आसपास होगी। यानी प्रति महीने लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए और साल का 18 लाख करोड़ रुपए अकेले इन मजदूरों की पेंशन पर खर्च होगा।

व यहां, जल पर न, जिस नाये न सतान का पारन  
मां रोती है, वहां पर कभी कल्प्याण नहीं हो सकता है।  
गाय मां है और बैल धर्म है। गाय के पंचगव्य से  
अनेकों प्रकार की औषधियां बनती हैं। गऊ पूजन व  
गोदान का विशेष महत्व होता है। भैंस पूजन का महत्व  
नहीं है। प्रातः उठकर गाय के शरीर पर हाथ फेरो,  
परिक्रमा करके चरण वंदना करो तथा एक मुट्ठी खास  
या एक रोटी गाय को हर रोज दें, ऐसा करने से प्रभु  
के अवश्य दर्शन होते हैं। रोगी गाय को औषधि व सेवा  
करने वाला व्यक्ति रोगमुक्त हो जाता है। वर्तमान में  
गोबर से निर्मित वस्तुएं, यथा आभूषण, राखी, छुमर,  
मूर्तियां, गमले एवं नेम प्लेट सर्वार्थिक चलन में हैं।  
अगर हम हिमाचल प्रदेश की वर्तमान स्थिति की बात  
करें तो यहां पर गौवंश की स्थिति ठीक नहीं है।  
सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस समय में लगभग  
10000 से अधिक गौवंश बेसहारा चारे तथा पानी की  
तलाश में इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, जो हमारे  
देवभूमि के लोगों के लिए बड़े ही दुःख और शर्म की  
बात है। पूर्व में रहे ग्रामीण पशुपालन मंत्री श्री वीरेंद्र  
कंवर और पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल  
प्रदेश गौसेवा आयोग की स्थापना करके इन बेसहारा  
गौवंश को आश्रय देने के लिए प्रदेश में कई स्थानों पर  
बड़ी-बड़ी गऊ सँकुरी और गौशालाओं की स्थापना  
करके बड़ा साहसिक और नेक कार्य किया है। लेखक  
ने सरकार के वर्तमान कृषि एवं पुशपालन मंत्री को  
14.11.2023 को बेसहारा गौवंश के लिए गौसेवा

A close-up photograph of several white and yellow capsules scattered on a blue surface, representing pharmaceuticals.



जापान द्वारा नाशिलाएं ये गुण सहजे बनाने तक गौसेवकों की भर्ती करने वारे कुछ मुश्खलाएं प्रदेश में जो लगभग 10000 से ज्यादा बेसहारा गौवंश हैं, इनकी सेवा के लिए गौसेवा आयोग प्रत्येक जिले के प्रत्येक विकास खंड में तीन-तीन बड़ी गौशालाएं बनाएं, ताकि इन अभागों पालतू छोड़े हुए बेसहारा गौवंश को इनका खोया हुआ रैन-बसरेरा दोबारा मिले सके। दो, इन 10000 बेसहारा गौवंश की सेवा के लिए गौसेवा आयोग 1000 गौसेवकों की भर्ती करे, यानी प्रत्येक 10 गौवंश पर एक गौसेवक नियुक्त हो, जिसकी तनखाह प्रति महीना 6000 रुपए हो तथा साथ में मुफ्त रिहायश और भोजन की व्यवस्था हो। तीन, इन गौसेवकों को आठ या दस साल बाद की सेवा के बाद प्रदेश सरकार अपने विभागों या बोर्डों में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों में नियुक्त करने का प्रबन्ध करे। चार, जितने भी लोगों ने प्रदेश में गाय या बैल पाल रखे हैं, उन सबकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए यानी उन सबके गौवंश कार्ड बनाए जाने चाहिए, जैसे आदिमियों के राशन कार्ड बनाए जाते हैं। यह कार्य पशुपालन विभाग द्वारा पंचायतों के सहयोग से किया जाना चाहिए। पांच, अगर कोई पशुपालक अपने गौवंश को बेसहारा छोड़ता है तो ऐसे पशुपालक को पहली बार 15000 रुपए, दूसरी बार 20000 रुपए, तीसरी बार 25000 रुपए और एक साल की सजा भी होनी चाहिए। छह, प्रदेश सरकार राज्य में गोमूत्र आधारित कोई बड़ी आयुर्वेदिक फर्मेसी स्थापित करे ताकि गौवंश पालने वालों को आर्थिक सहायता भी मिल सके और प्रदेश की जनता को आयुर्वेदिक औषधियां भी मिल सके। सात, पशुपालकों को बढ़िया बैल पालने पर गौसेवा आयोग द्वारा सालाना लगभग 6000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए। आठ, जो शामलात भूमि सरकार के पास वनों के साथ है, वहां सरकार उस भूमि का अधिग्रहण करके या किसानों से बंजर भूमि लेकर गौशालाएं बनाए। नौ, सरकार शराब की बिक्री से अद्वैत रुपए प्रति बोतल की सैस को बढ़ाकर 10 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से गौ कल्याण कोष के लिए निर्धारित करे। दस, प्रदेश सरकार बड़े मंदिर ट्रस्टों की आमदन के 15 प्रतिशत हिस्से को बढ़ाकर 25 प्रतिशत गौ कल्याण कोष के लिए निर्धारित करे। एकांश, प्रदेश सरकार विधानसभा में कानून बनाकर गौ कल्याण कोष की बढ़ोत्तरी के लिए प्रत्येक विधायक तथा मंत्री से पांच-पांच हजार रुपए दान लेने की व्यवस्था शुरू करे। बारह, इसी प्रकार प्रदेश सरकार गौ कल्याण कोष के लिए प्रदेश के सारे पहली श्रेणी के अधिकारियों से 500 रुपए, दूसरी श्रेणी वालों में से 250 रुपए, तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों से 100 रुपए तथा चतुर्थ श्रेणी वालों से 50 रुपए प्रति महीना दान लेने की व्यवस्था शुरू करे।

## संक्षिप्त समाचार

दिगंबर जैन सोशल ग्रुप सम्मति की सदस्य परिचय पुस्तिका का हुआ विमोचन



जयपुर (विश्व परिवार)। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप सम्मति द्वारा सत्र 2023 के सदस्यों की परिचय पुस्तिका का विमोचन समरोह के अंतर्गत किया गया। संस्थापक अध्यक्ष राकेश- समता गोदिका के अनुसार मुख्य समन्वयक दर्शन- विनाना बाकलीवाल के नेतृत्व में संयोगक मंडल मनीष- शोभा लोंगा, राजेश- रानी पाटनी, अनिल- प्रेमा रावका, संजय- ज्योति छावड़ा, कमल- मंजू ठालिया, राकेश- रेणु संभा, नीता- मीना पांडिया की टीम ने ग्रुप की सभी गतिविधियों को समाहित करते हुए मुंदर समाजिक का प्रकाशन किया है। निवन्तीन सचिव अनिल- निशा संभी के अनुसार प्रमुख समाज सेवी प्रोग्राम प्राइडिंग, समाचार जैन के संपादक शेलेंड गोधा, जैन चंद झांझी, ग्रुप संरक्षक सुनेंद्र पांडिया, जैनेंद्र जैन, राजस्थान जैन सभा के अध्यक्ष सुभाष चंद जैन, राजस्थान युवा महासभा के अध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री विनोद जैन कोट्यावदा सहित अनेक गणमान्य नागरिक इस अवसर पर उपस्थिति रहे।

**शोक सभा में चौधरी जयकुमार जैन एडवोकेट नवरत्न को दी श्रद्धांजलि**

ललितपुर (विश्व परिवार)। सकल दिगंबर जैन समाज की शोक सभा में मोहल्ला सरफयाना तालबहट निवासी चौधरी जयकुमार, अलोक कुमार, अनून कुमार, अभय कुमार जैन के पूजनीय पिताजी एवं पूर्व केंद्रीय राजनीति मंत्री जयकुमार जैन एडवोकेट नवरत्न के 82 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। अहिंसा सेवा संगठन के संस्थापक विश्वाल जैन पवा ने इसे समाज एवं नरारोपण के लिये अपर्णा प्रथा की शोक व्यक्ति बताया। एडवोकेट जयकुमार जैन, अविवाहित कुमार, श्रीयांशु जैन, सुशील मोदी, प्रदीप एड, विकास पवा, अजय जैन अन्जू, धरणेंद्र कुमार, देवेंद्र बसार, मनोज कुमार, राकेश मोदी, मेघराज जैन, पुष्पेंद्र कुमार, चक्रेश जैन, अरुण कुमार, कपिल मोदी, संजय कुमार, श्रीयांशु जैन, सुशील मोदी, प्रदीप एड, विकास पवा, अजय जैन अन्जू, धरणेंद्र जैन, हिंतेंद्र कुमार, सारैभ पवेया, अमितेष जैन, अविवाहित कुमार, विकास भंडारी, सीमें जैन, रुपेश भंडारी, रंजीत जैन, अनुराग मिद्या, राजेंद्र जैन, रोहिंद्र कुमार, राहुल जैन, सौरभ मोदी, अरविंद, अंजेश, अर्योग मोनू, अरविंद, अंजेश, प्रिंस जैन, अधिष्ठक जैन, अशीष कुमार, अकिंत जैन, वैभव जैन, प्रमिला राजा, विनय, अक्षत, अमर, शुभम, सरल, पारस आदि प्रमुख रहे।

**कलेक्टर डॉ. सिंह के निर्देश पर कौविड-19 के मृतकों का हुआ अंतिम संस्कार**



रायपुर (विश्व परिवार)। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर आज कौविड-19 से तीन मृतकों का दोवें नाम धन्ति धार्मिक दर्शन में अंतिम संस्कार किया गया। मृतकों के परिजनों की सहमति ली गई, फिर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की गई। अंतिम संस्कार कौविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए किया गया। इस दीरान जिला प्रशासन, नगर निगम, मेकाहारा, पुलिस विभाग की टीम उपस्थित रही। गौतमतल है कि कौविड-19 से मृत तीन लोगों के शव मेकाहारा के चीरघर में रखे गए थे। जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों की जानकारी जुटाकर सहमति ली और उनका अंतिम संस्कार किया गया।

**भाजपा बताएं मोदी सरकार ने 70 वर्ष से ऊपर आयु के बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित वर्यों रखा: कांग्रेस**

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा की भाजपा को चुनाव में हार नहर आ रही है। इसलिए अब उन्हें बुजुर्गों की याद आ रही है अब बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधा देने का दावा कर पैरम भरवा रही है। देश के करोड़ों बुजुर्ग भाजपा के देख चुके हैं। अब बुजुर्गों भी भाजपा के खिलाफ महिलाओं से फर्जी भाजपा के खिलाफ मिलने वाली सब्जिकी को खाना चाहिए कि मोदी सरकार युवाओं, बुजुर्गों, किसान, महिला, मर्दूर, के लिये कोई काम नहीं किया है। जिला प्रशासन के परिषद नामी विधायिकों ने बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित वर्यों रखा है? इन में यात्रा के दौरान बुजुर्गों को मिलने वाली सब्जिकी को खाना चाहिए कि मोदी सरकार युवाओं, बुजुर्गों, किसान, महिला, मर्दूर, के लिये कोई काम नहीं किया है। जिला प्रशासन ने कहा की भाजपा को चुनाव में हार नहर आ रही है। अब उन्हें बुजुर्गों की याद आ रही है। जिला प्रशासन के परिषद नामी विधायिकों ने बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित वर्यों रखा है? इन में यात्रा के दौरान बुजुर्गों को मिलने वाली सब्जिकी को खाना चाहिए कि मोदी सरकार युवाओं, बुजुर्गों, किसान, महिला, मर्दूर, के लिये कोई काम नहीं किया है। जिला प्रशासन ने कहा की भाजपा को चुनाव में हार नहर आ रही है। अब उन्हें बुजुर्गों की याद आ रही है। जिला प्रशासन के परिषद नामी विधायिकों ने बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित वर्यों रखा है? इन में यात्रा के दौरान बुजुर्गों को मिलने वाली सब्जिकी को खाना चाहिए कि मोदी सरकार युवाओं, बुजुर्गों, किसान, महिला, मर्दूर, के लिये कोई काम नहीं किया है। जिला प्रशासन ने कहा की भाजपा को चुनाव में हार नहर आ रही है। अब उन्हें बुजुर्गों की याद आ रही है। जिला प्रशासन के परिषद नामी विधायिकों ने बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित वर्यों रखा है? इन में यात्रा के दौरान बुजुर्गों को मिलने वाली सब्जिकी को खाना चाहिए कि मोदी सरकार युवाओं, बुजुर्गों, किसान, महिला, मर्दूर, के लिये कोई काम नहीं किया है। जिला प्रशासन ने कहा की भाजपा को चुनाव में हार नहर आ रही है। अब उन्हें बुजुर्गों की याद आ रही है। जिला प्रशासन के परिषद नामी विधायिकों ने बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित वर्यों रखा है? इन में यात्रा के दौरान बुजुर्गों को मिलने वाली सब्जिकी को खाना चाहिए कि मोदी सरकार युवाओं, बुजुर्गों, किसान, महिला, मर्दूर, के लिये कोई काम नहीं किया है। जिला प्रशासन ने कहा की भाजपा को चुनाव में हार नहर आ रही है। अब उन्हें बुजुर्गों की याद आ रही है। जिला प्रशासन के परिषद नामी विधायिकों ने बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित वर्यों रखा है? इन में यात्रा के दौरान बुजुर्गों को मिलने वाली सब्जिकी को खाना चाहिए कि मोदी सरकार युवाओं, बुजुर्गों, किसान, महिला, मर्दूर, के लिये कोई काम नहीं किया है। जिला प्रशासन ने कहा की भाजपा को चुनाव में हार नहर आ रही है। अब उन्हें बुजुर्गों की याद आ रही है। जिला प्रशासन के परिषद नामी विधायिकों ने बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित वर्यों रखा है? इन में यात्रा के दौरान बुजुर्गों को मिलने वाली सब्जिकी को खाना चाहिए कि मोदी सरकार युवाओं, बुजुर्गों, किसान, महिला, मर्दूर, के लिये कोई काम नहीं किया है। जिला प्रशासन ने कहा की भाजपा को चुनाव में हार नहर आ रही है। अब उन्हें बुजुर्गों की याद आ रही है। जिला प्रशासन के परिषद नामी विधायिकों ने बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित वर्यों रखा है? इन में यात्रा के दौरान बुजुर्गों को मिलने वाली सब्जिकी को खाना चाहिए कि मोदी सरकार युवाओं, बुजुर्गों, किसान, महिला, मर्दूर, के लिये कोई काम नहीं किया है। जिला प्रशासन ने कहा की भाजपा को चुनाव में हार नहर आ रही है। अब उन्हें बुजुर्गों की याद आ रही है। जिला प्रशासन के परिषद नामी विधायिकों ने बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित वर्यों रखा है? इन में यात्रा के दौरान बुजुर्गों को मिलने वाली सब्जिकी को खाना चाहिए कि मोदी सरकार युवाओं, बुजुर्गों, किसान, महिला, मर्दूर, के लिये कोई काम नहीं किया है। जिला प्रशासन ने कहा की भाजपा को चुनाव में हार नहर आ रही है। अब उन्हें बुजुर्गों की याद आ रही है। जिला प्रशासन के परिषद नामी विधायिकों ने बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित वर्यों रखा है? इन में यात्रा के दौरान बुजुर्गों को मिलने वाली सब्जिकी को खाना चाहिए कि मोदी सरकार युवाओं, बुजुर्गों, किसान, महिला, मर्दूर, के लिये कोई काम नहीं किया है। जिला प्रशासन ने कहा की भाजपा को चुनाव में हार नहर आ रही है। अब उन्हें बुजुर्गों की याद आ रही है। जिला प्रशासन के परिषद नामी विधायिकों ने बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित वर्यों रखा है? इन में यात्रा के दौरान बुजुर्गों को मिलने वाली सब्जिकी को खाना चाहिए कि मोदी सरकार युवाओं, बुजुर्गों, किसान, महिला, मर्दूर, के लिये कोई काम नहीं किया है। जिला प्रशासन ने कहा की भाजपा को चुनाव में हार नहर आ रही है। अब उन्हें बुजुर्गों की याद आ रही है। जिला प्रशासन के परिषद नामी विधायिकों ने बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित वर्यों रखा है? इन में यात्रा के दौरान बुजुर्गों को मिलने वाली सब्जिकी को खाना चाहिए कि मोदी सरकार युवाओं, बुजुर्गों, किसान, महिला, मर्दूर, के लिये कोई काम नहीं किया है। जिला प्रशासन ने कहा की भाजपा को चुनाव में हार नहर आ रही है। अब उन्हें बुजुर्गों की याद आ रही है। जिला प्रशासन के परिषद नामी विधायिकों ने बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित वर्यों रखा है? इन में यात्रा के दौरान बुजुर्गों को मिलने वाली सब्जिकी को खाना चाहिए कि मोदी सरकार युवाओं, बुजुर्गों, किसान, महिला, मर्दूर, के लिये कोई काम नहीं किया है। जिला प्रशासन ने कहा की भाजपा को चुनाव में हार नहर आ रही है। अब उन्हें बुजुर्गों की याद आ रही है। जिला प्रशासन के परिषद नामी विधायिकों ने बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित वर्यों रखा है? इन में यात्रा के दौरान ब





